

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिपा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 11 अप्रैल 2024 गुरुवार

सम्पादकीय

विकास और पर्यावरण

दशकों से निरंतर बहस का विषय रहा है कि हमारी प्राथमिकता विकास हो या पर्यावरण। जिन समाजों को विकास के चलते विस्थापन झेलना पड़ता है, वे विकास को विनाश की संज्ञा देते रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों व पर्वतीय इलाकों में बांध व अन्य बड़ी विकास परियोजनाओं के अस्तित्व में आने पर विरोध के सुर गाहे-बगाहे उभरते रहे हैं। ऐसे में न्यायिक फ़ैसले सरकारों की मनमानी पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा निर्णय आया है जिसे विकास तथा पर्यावरण संरक्षण व पारिस्थितिकीय संतुलन की दृष्टि से नज़ीर का फ़ैसला कहा जा रहा है। यह फ़ैसला एक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट और दुर्लभ प्रजाति के पक्षी सोन चिड़िया को लेकर है। दरअसल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिड़िया के अस्तित्व के लिये राजस्थान और गुजरात के इलाके में घातक माने जा रहे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की ट्रांसमिशन लाइनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अनुकरणीय फ़ैसला दिया है कि जो आने वाली पड़ियों के लिये मार्गदर्शक साबित हो सकता है। जो न्यायिक दृष्टि में भी बदलाव का पर्याय है। दरअसल, अब तक अधिकांश अदालत के फ़ैसले पर्यावरण के पक्ष में या फिर विकास के पक्ष में जाते रहे हैं। लेकिन अदालत ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के लिये विकास जरूरी है तो पारिस्थितिकीय संतुलन भी जरूरी है। अदालत के फ़ैसले के आलोक में मौजूद ग्लोबल वार्मिंग संकट और उसके दूरगामी प्रभाव भी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने जलवायु परिवर्तन तथा पारिस्थितिकीय अस्तित्व को देश के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की दृष्टि से जोड़कर देखा है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोर्ट ने अपना पुराना फ़ैसला भी इस संकट को दूर करने के लिये बदला है। दरअसल, गुजरात व राजस्थान के करीब नब्बे हजार वर्ग किमी के क्षेत्र में विस्तृत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट दुर्लभ पक्षी सोन चिड़िया के अस्तित्व पर खतरा बन रहा था। जिस पर शीर्ष अदालत ने एक फ़ैसले में रोक लगा दी थी।

दरअसल, अदालत को तब बताया गया था कि विद्युत तारों के संपर्क में आने से इन पक्षियों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है। ये बिजली की तारें उस क्षेत्र में लगायी हुई हैं जहां इन पक्षियों का आना-जाना होता है, जिनसे ये पक्षी बड़ी संख्या में टकराकर दम तोड़ देते हैं। अदालत के फ़ैसले के चलते सौर ऊर्जा की महत्वाकांक्षी योजना पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। दरअसल, यह इलाका सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से खासा उर्वर माना जाता है। ऐसे में अदालत ने यह महत्वपूर्ण फ़ैसला दिया कि जहां एक ओर सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य भी पूरे हों, वहीं पक्षियों के अधिवास व जीवन की भी रक्षा हो सके। बीच का रास्ता निकालते हुए अदालत ने फ़ैसला दिया कि 77 हजार वर्ग किमी क्षेत्र में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन प्रमाणी रहेगी। वहीं दूसरी ओर तेरह हजार वर्ग किमी के क्षेत्र को इन दुर्लभ पक्षियों के अधिवास के रूप में सुरक्षित करने को कहा है। अदालत का मानना था कि सरकारें ग्लोबल वार्मिंग के संकट के चलते अपनी रीति-नीतियों में जो परिवर्तन कर रही हैं, उन्हें संविधान के मूल अधिकारों से जोड़ने की जरूरत है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से आम लोगों का जीवन गहरे तक प्रभावित हो रहा है। वहीं जीवन यापन के लिये पर्याप्त सौर ऊर्जा की लोगों को लिये उपलब्धता सुनिश्चित करना भी सरकारों का प्राथमिक दायित्व है। यह मामला लोगों के जीवन के अधिकार से जुड़ा भी है। आने वाले सालों में देश की ऊर्जा जरूरतों में व्यापक वृद्धि का आकलन किया जा रहा है। जिसे वैकल्पिक ऊर्जा के जरिये ही पूरा किया जा सकता है। जिसमें सौर ऊर्जा की बड़ी भूमिका होगी। जो देश के पर्यावरण प्रदूषण को घटाने में भी सहायक हो सकती है। साथ ही भारत को वैश्विक संस्थाओं को जोीवाश्म ईंधन का उपभोग घटाने के वायदे को भी पूरा करना है। इसके लिये जरूरी है कि हम रसच्छ ऊर्जा के अधिक से अधिक उत्पादन को अपनी प्राथमिकता बनाएं। यह हमारे नीति-निर्णयों के लिये भी मार्गदर्शक फ़ैसला है कि हम अपने पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षित करते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ें।

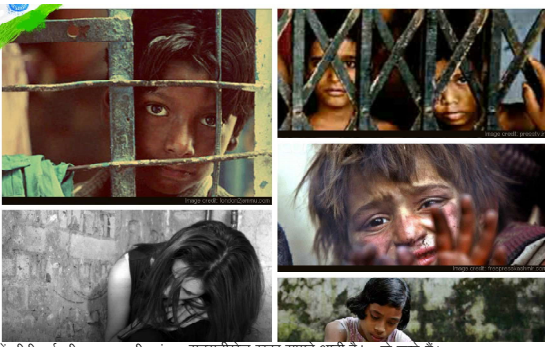
बाल-तस्करी का बढ़ता दायरा



—ललित गर्ग—

देश की राजधानी दिल्ली में तमाम जांच एजेंसियों की नाक के नीचे नवजात बच्चों की खरीद-फ़रोख़ की मंडी चल रही थी जहां दसमुहरे एवं मासूम बच्चों को खरीदने-बेचने का धंधा चल रहा था। दिल्ली की बच्चा मंडी के शर्मनाक एवं खौफनाक घटनाक्रम का पदापाश होना, अमानवीयता एवं संवेदनहीनता की चरम परकाष्ठा है। जिसने अनेक जलंत सवालों को खड़ा किया है। आखिर मनुष्य क्यों बन रहा है इतना कर, अनैतिक एवं अमानवीय? संसमूह पैसे का नशा जग, जहां, जिसके भी सर चढ़ता है वह इंसान शैतान बन जाता है। दिल्ली के केवलापुरम इलाके में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने छापेमारी कर ऐसे ही शैतानी के कुकृत्यों का भंडाफोड़ किया और एक महिला समेत सात लोगों को गैरहाथ गिरफ्तार किया, इसके साथ ही तीन नवजात शिशुओं को उनके चंगुल से बचाया। आरक्षियों में एक अस्तिस्टेंट लेबर कमिश्नर को इस धंधे का मास्टर मस्जद माना जा रहा है। न केवल दिल्ली वालों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए यह खबर घिंता पैदा करने वाली ही नहीं है, बल्कि खौफ पैदा करने वाली भी है।

दिल दखले देने वाली इस घटना



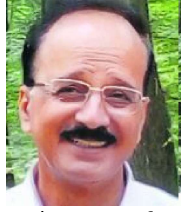
में सीबीआई की अब तक की जांच से पता चलता है कि आरोपी फ़ैसलूक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन के माध्यम से बच्चे गोद लेने के इच्छुक निस्तान दंपतियों से जुड़ते हैं। आरोपी दंपती तौर पर वास्तविक माता-पिता के साथ-साथ सेरेगैट माताओं से भी नवजात बच्चे खरीदते थे। इन नवजात बच्चों को घर से छह हाथ रुपा में बेच दिया जाता था। जांच से जुड़े सीबीआई अधिकारियों के अनुसार एजेंसी की गिरफ्त में आए आरोपी बच्चों को गोद लेने से संबंधित फ़र्जी दस्तावेज़ तैयार कराते थे। आरोपी कई निस्तान दंपतियों से लाखों रूपय की ठगी करने में भी सफल है। इस गिराह के तार कहां-कहां है इसकी भी कड़ियां जोड़ी जा रही है। यह गिराह आईपीएफ के माध्यम से युवतियों को गमधारा करवा था फिर इन शिशुओं को बेचता था। गरीब माता-पिता से भी बच्चे खरीदे जाते थे। बच्चों की खरीद-फ़रोख़ और बच्चों की तस्करी एक ऐसी समस्या है जिस पर तभी ध्यान जाता है जब कोई

संसन्नेलीख खबर सामने आती है। अर्थ की अंधी दौड़ में इंसान कितने क्रूर एवं अमानवीय घटनाओं को अंजाम देने लगा है कि चेहरे ही नहीं चरित्र तक अपनी पहचान खोने लगे हैं। नीति एवं निष्ठा के केन्द्र बदलने लगे हैं। मानवीयता एवं नैतिकता की नींव कमजोर होने लगी है। आदमी इतना खुदगर्ज बन जाता है कि उसकी सारी संवेदनाएं सूख जाती हैं। बाल तस्करी को खिज़ाफ़ कई सख्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद भारत में यह समस्या नासूर बनती जा रही है। नवजात बच्चे नष्ट होने वाले गिराह के पदार्थापन से फिर यह तथ्य प्रमत्त है कि बच्चों के मनुष्य से खिलवाड़ करने वालों में कानून का कोई खौफ़ नहीं है। बच्चों की तस्करी पर भारी जुर्माने के साथ उकड़ेद तक का प्रावधान होने के बावजूद यह कड़वी हकीकत है कि ऐसे दस फ़ीसदी से भी कम मामले दायित्व को सजा तक पहुंच पाते हैं। मुबददों की पैरवी सही तरीके से नहीं होने के कारण अपराधी बच निकलते हैं और वे फिर बाल तस्करी एवं बच्चों की खरीद-फ़रोख़ में लिप्त हो जाते हैं।

देश में युवाओं के एक वर्ग की सोच में बदलाव भी परेश रूप से बाल-तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। एक सर्वे में खुलासा हुआ था कि भारत के नौ फ़ीसदी युवा शादी तो करना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। संतान पुच्छ के लिए उन्हें बच्चे खरीदने से प्रेरित है। देश के ढाई करोड़ से ज्यादा अनाथ बच्चों में से किसी को गोद लेने का विकल्प होने के बावजूद ऐसे युवा कई बार बाल तस्करी करने वालों से संपर्क तक साध लेते हैं। बाल तस्करी भारत की एक उमरती एवं ज्वलंत समस्या है। यह केवल भारत की ही नहीं, दुनिया की बड़ी समस्या है। पिछले साल एक एनजीओ की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2016 से 2022 के बीच बाल तस्करी के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, बाल-तस्करी भारत की एक उमरती एवं ज्वलंत समस्या है। यह केवल भारत की ही नहीं, दुनिया की बड़ी समस्या है। पिछले साल एक एनजीओ की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2016 से 2022 के बीच बाल तस्करी के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की थीं। बचपन अगर बाल तस्करी के बीच फंसेकर रह जाए तो बच्चा अपने बचपन, क्षमता और मानवीय गरिमा के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक विकास से भी वंचित रह जाता है। गैरसलब है कि बच्चों के घरोरु काम, विभिन्न श्रेणों में बाल श्रम, बीच मांगना, अंग तस्करी और व्यावसायिक यौनकर्म जैसी अंधे गतिविधियों बाल तस्करी की कोख से ही जन्म लेती हैं। सरकार और समाज को इससे मिलकर निपटना होगा। इस समस्या की जड़ में गरीबी भी है। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यावहारिक और दोस्त नीति बनाई जानी चाहिए कि बाल तस्करी के अमूल्य उन्मूलन की जमीन तैयार हो सके।

इसे देश की विद्वानों कहें या दुनिया की आज बहुत से अजन्मे जन्म-मृत्यु से जुड़ने लगे हैं। जीवन लेने के बाद इस देश में बच्चों को बेच दिया जाता है या ऐसे बच्चों का एक बहुत बड़ा वर्ग चौराहों, रेलवे स्टेशन, गली-मंडल में भीख मांगता मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का बचपन हॉटलों पर काम करते या जुड़े बच्चे होते हुए या फिर काला कोटरियों में जीवन बिताते हुए कट जाता है। यों भी कह सकते हैं कि उन्मत्त जीवन आज अंधेरे में ढक रहा है, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत का बचपन आर्थिक कारणों से घायल है। बच्चों को बेचे और खरीदे जाने में जितने लोग, जिस तरह शामिल होते थे, वह यह नवते भारत के माल पर एक बन्दुगना दाग है। क्यों कानून का डर ऐसे अपराधियों को नहीं होता? क्यों सरकार की अमूल्यवीय सोच क्यों पतन रही है?

शहरी जल संकट की चुनौतियां



—देविंदर शर्मा—

कई साल पहले, मैंने टाइम्स पत्रिका में एक बहुत दिलचस्प लेख पढ़ा था 'कैप टाउन के भारी जल संकट के बीच जीना कैसा होता है।' इस वर से कि आने वाले महिनों में इस सूख जाएगा, दक्षिण अफ्रीका फेला शहर बन गया जिनमें न केवल चेतावनी दी, बल्कि यह भी बताया कि जब नल सूख जाएंगे और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल डूबे से भी नहीं मिमांगे तो यह कितना भयानक होगा। पिछले कुछ हप्तों में, बंगलुरु जिस गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, उस पर कई लेख आए हैं, जिनमें शहर के कुछ हिस्सों में ऊंची इमारतों के निवासियों को पड़ेसी मॉल में शौचालय का उपयोग करने के लिये मजबूर होने की खबरें शामिल हैं। जो कैप टाउन के दुखद कल्पनाओं वाले परिदृश्य के समान हैं। विशेष रूप से देश के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित एक लेख 'जब नल सूख जाते हैं' में दिखाया गया कि कैसे कभी झीलों का शहर, जैसा कि इसे कभी जाना जाता था, एक शहरी क्रीक का जंगल बन गया, आर्थिक विकास का शिकार हो गया। अजीब प्रेमी विधिविधालय की सीमा मुसलने ने अपने विचारलेख लेख में बतलाते हैं। यह कहते हैं कि 'आर' यानी- हमारे रिश्ते, हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां' दु पर विचार करना के लिए प्रेरित किया कि कैसे शिक्षित लोगों ने समझां को इतनी तेजी से घूमल होने दिया है। वे ही पर मुझे लगता है कि बंगलुरु के जल संकट की तुलना पंजाब के मूल में धिताजनक निरापट से करना महत्वपूर्ण हो गया है। पानी की अधिक खपत करने वाली धान की खेती को तेजी से भूजल की कमी के पीछे प्रमुख कारण बताया जा रहा है, जबकि 138 विकास खंडों



में से 109 से अधिक ब्लॉक पहले से ही डाकें जा चुके हैं, जहां निकासी की दर पुनः आपूर्ति की दर से अधिक है। इन दोनों की तलाश में किसानों को अधिक गहराई तक जाने के लिए स्वामित्वित बल स्थापित करने के लिए उकसाया है और कई मामलों में इसे सीधे जलोत्पन्न चट्टानों परल से प्राप्त किया है। कई अध्ययनों से पता चला है कि पंजाब का भूजल जल्द ही खत्म हो जाएगा, कुछ का तो यह भी अनुमान है कि भूजल 17 साल से अधिक नहीं टिकेगा। पंजाब में, कई दशकों से फसल विविधीकरण का सुझाव दिए जाने बादवृद्ध, धान का क्षेत्रफल असल में बढ़ा है। इस वर्ष, पंजाब में धान का ससय अधिक रकबा और सर्वाधिक उपज भी दर्ज की गई। हालांकि ऐसा माना जाता है कि धान की फसल में 1 किलो चालव पैदा करने के लिए 5,000 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। पंजाब केंद्रीय भंडार में चालव का सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है। इसलिए यह खाना सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर भी, ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र व राज्य सरकारें धान के लिए आर्थिक रूप से कोसों लाभ विकल्प लेकर नहीं आई हैं, फसल विविधीकरण अभी तक नहीं जमाना सका है। आश्चर्य होता है कि अगर फसल विविधीकरण पंजाब के लिए एक समाधान है, तो बंगलुरु के मामले में यह शहर विविधीकरण क्यों नहीं हो सकता? महानगर की वहन क्षमता को देखते हुए, शहर अब चरमरा रहा है। 2011 में 8.7 मिलियन से,

के जन आंदोलन के बावजूद प्रशासन नींद में है। अब भी, उदाहरण के लिए, सभी की निगाहें शहर के पूर्वी हिस्से में जुनसांडा झील के 24 एकड़ में आवास परिसर स्थापित करने पर हैं, जो सूख जा रहा है। आईटी हब के आसपास, हलनायकनहल्ली झील सभी प्रकार के मलबे और कचरे का डंपिंग ग्राउंड है। जैसा कि हमने न केहा, 'कई झीलें बारम्बारी लव गई हैं— कचरे और मलबे के साथ।' धान की बढ़ती खेती के साथ-साथ पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए भी दोषी ठहराया जाता है। ऐसी गलती करने वाले किसानों के 'खिलाफ एकआईआर, जुमना, राजस्व रिडॉर्में में रेंड एंटी और सफ़्टवेयर इन्फ्रा की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने जैसे कुछ अन्य कदम उठाए जाते हैं। मगर प्रशासनिक अधिकारियों और रियल एस्टेट कंपनियों पर एकआईआर क्यों नहीं दर्ज की जाती जिन्होंने उस जमीनी पर कब्जा कर लिया जहां पर कभी झीलें और जलाशय होते थे। पर्यावरणीय युक्त के लिए जब शहरी आंदोलन और किसानों को दखित करने की बात आती है तो दोहरे मानदंड किसलिए होने चाहिए? शहरियों से नरमी का बर्ताव किया जाता है जबकि सभी तरह की दबावकत कारवाइं फ़िरांगों पर जो जाती है वह बिल्कुल ही आर्थिक गतिविधि के लिए हमेशा पब्लिक-ग्राइवेट्टेड पार्टनरशिप की बात की जाती है। परंतु जल संकट जैसी बड़ी समस्याओं को संबोधित करने की बात आती है तो निजी क्षेत्र किसी साझे प्रयास में हाथ मिलाते के लिए इच्छुक नजर नहीं आता है। रोचक तौर पर, एक फ़ैसलूक पोस्ट में सुझाव दिया गया था कि नारायणमूर्ति ने अपने 6 माह के पोते को 240 करोड़ रूपय की कीमत का जो शेरव निपट किया था उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता था यदि ऐसी राशि उस भीषण जल संकट के लिए दानस्वरूप प्रदान की जाती जिसे कअसर शहर के मनुष्य पर हो रहा है। बहरहाल, जिस शहर में आप रहते हैं उसके किसी असाधारण संकट की चपेट में आने के साथ उसके लिए खड़े होने की सामंजसिक और निजी क्षेत्र की निश्चित तौर पर सामूहिक जिम्मेदारी होती है—लेखक कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं।

होमियोपैथी औषधियों के हैनिमैन जी जनक कहाये

प्रमुदित धरा हुई रसवती। हैनिमैन की आज जन्मती। डॉ० हैनिमैन जी सचमुच। त्याग दया के थे प्रतिमूर्ति। अद्भुत उर्जा उनके भीतर। थी कितनी उनमें स्फूर्ति। होमियोपैथी औषधियों के। हैनिमैन जी जनक कहाये। अपनी कर्मठता से जग को यह सस्ता उपचार बताए। होमियोपैथी औषधि के थे। डॉ० हैनिमैन निर्माता। उनके ऊपर आज कर्म करती। गर्व हमारी भारत माता। आओ डॉ० हैनिमैन का। जन्म दिवस हम लोग मनाये। उनके श्री चरणों में पर्मा। श्रद्धा रूपी सुमन चढ़ाए।



(डॉ० वी० के० वर्मा) आयुष चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय बस्ती नोडल अधिकारी मेम स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष अध्यक्ष-रिसर्च सोसायटी ऑफ होम्योपैथी बस्ती, (स. प्र.)

